tax-payer and tax-taker हो सके, इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यकता महसूस की गयी है। हमारे विभाग ने भी इसे महसूस किया है और उसके आधार पर NCERT से और बाकी जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वह हम निश्चित तौर पर करेंगे।

DR. NARENDR JADHAV: Sir, tax-payer education is only a small part of financial literacy. The reply given here talks about supplementary material placed in secondary school education. This is necessary, but is it sufficient? Sir, in our country, financial literacy is very, very poor. The latest data suggests that regarding financial literacy, the national average is only 20 per cent and among females, it is only 16 per cent. In Bihar, among females, the financial literacy is only 4 per cent. Sir, financial literacy is a core life skill and when the Government is making so much efforts for financial inclusions through plans like *Jan Dhan Yojana* etc., should they also not be making concerted efforts for improving the overall financial literacy?

श्री उपेन्द्र कुशवाहाः महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य का कहना बहुत ही उचित है। न सिर्फ NCERT, बल्कि NIOS के माध्यम से भी financial literacy, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स में, जहां गांव की महिलाएं भी आती हैं और दूसरे लोग भी आते हैं, देने का काम पहले से चल रहा है, लेकिन इसको और व्यापक बनाया जाएगा।

श्री अजय संचेतीः सर, दुनिया में आज liberal education बहुत तेजी से पढ़ायी जा रही है। हम लोग देखेंगे कि हमारे यहां graduates और post-graduates जितनी चीज़ें जानते हैं, विदेशों में, बाहर के देशों में जो 12वीं पास कर लेता है, उसे हमसे ज्यादा जानकारी होती है और वह काम में भी लग जाता है। मैं सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं - कुछेक private universities ने हमारे यहां liberal education शुरू भी की है, ऐसी universities भी खुली हैं, तो self employment को बढ़ाने के लिए tax-payer education के साथ-साथ क्या liberal education को भी government institutions में सरकार बढ़ावा देने जा रही है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहाः सर, आवश्यकतानुसार जो भी हम महसूस करते हैं या कहीं से भी जो अच्छे सुझाव आते हैं, उनके आधार पर जो कुछ किया जा सकता है, वह हम करते रहते हैं। माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उसके आधार पर भी निश्चित रूप से कुछ करने की जरूरत है, ऐसा हम महसूस करते हैं।

शिक्षा के केन्द्र के रूप में रांची और जमशेदपुर

*199. **श्री प्रेम चन्द गुप्ता** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड के रांची और जमशेदपुर को शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने झारखंड राज्य में कतिपय केन्द्रीय संस्थाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से कुछ, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची और रांची केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने धनबाद स्थित भारतीय खनि विद्यापीठ स्कूल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदलने के लिए कार्रवाई की है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सरकार ने रांची और जमशेदपुर में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं जैसेकि स्वायत्त रांची कॉलेज का विश्वविद्यालय में उन्नयन, रांची विश्वविद्यालय और कोलहन विश्वविद्यालय के लिए अवसंरचना अनुदान, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय और करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर तथा सेंट जेर्वियस कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, निर्मला कॉलेज और योगदा सत्संग कॉलेज, रांची को अवसंरचना अनुदान और जमशेदपुर में नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 133.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

Ranchi and Jamshedpur as educational hubs

†*199. SHRI PREM CHAND GUPTA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has approved a proposal for developing Ranchi and Jamshedpur in Jharkhand as educational hubs; and

(b) if so, the details thereof and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MAHENDRA NATH PANDEY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. At present no such proposal is pending with the Central Government. However, Central Government has sanctioned certain central institutions in the State of Jharkhand. Some of these are Indian Institute of Management at Ranchi, Indian Institute of Information Technology at Ranchi and Central University in Ranchi. Further, Government has also moved to convert Indian School of Mines at Dhanbad into an Indian Institute of Technology. Under the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, Government has sanctioned an outlay of Rupees 133.00 Crores for various educational institutions in Ranchi and Jamshedpur such as upgradation of autonomous Ranchi College to University, infrastructure grant to Ranchi University and Kolhan University, infrastructure grant to Jamshedpur Women's College and Karim City College at Jamshedpur and St. Xavier's College, Marwari College, Nirmala College and Yogada Satsanga College at Ranchi and setting up of a new Engineering College at Jamshedpur.

† Original notice of the question was received in Hindi.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः मान्यवर, मेरा जो क्वेश्चन है, उसके पीछे एक सोच थी, जिसके ऊपर सरकार और मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे पाए हैं। झारखंड और बिहार जैसे जो पिछड़े प्रदेश हैं, वहां शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से वहां आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हजारों बच्चे हर साल बिहार और झारखंड से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में भी जाते हैं - हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये तो जानते ही हैं - आप भी जानते होंगे। मान्यवर, आप एक चीज़ मानेंगे कि अगर कोई क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में backward रहेगा... उसका आर्थिक विकास नहीं होगा। आर्थिक विकास नहीं होगा, तो उसका सोशल और कल्चरल विकास नहीं होगा। इससे नक्सलवाद और नक्सलवादी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मेरा यह प्रश्न था कि क्या आपने रांची और जमशेदपुर को educational hubs बनाने के लिए कुछ किया है? क्योंकि आपके मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि हम इसको educational hubs बना रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उस एरिया में जो नक्सलवाद की समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के सामने कोई ऐसी स्कीम है? क्या आपने विचार किया कि उस क्षेत्र को किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा सकता है, ताकि वहां आर्थिक विकास हो सके और बच्चे नक्सलवाद की ओर नहीं जाएं?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेयः उपसभापति महोदय, अभी वहां पर educatinal hubs बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहां के माननीय मुख्य मंत्री की अपने राज्य के संदर्भ में यह परिकल्पना है, यह उनका संदर्भ है। हमारी सरकार ने रांची और जमशेदपुर में कई तरह की ऐसी पहले की हैं। हमने वहां Indian Institute of Management, Ranchi; Indian Institue of Information Technology, Ranchi; केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची, अभी वहां झारखंड में भी Indian School of Mines को भी Indian School of Technology में प्रत्यारोपित करने की कार्रवाई की है, इस तरह वहां के लिए उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम किए हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उस राज्य को बहुत प्राथमिकता दी है। राज्य के आकलन के अनुसार प्रस्तुत योजना में 133 करोड़ रुपए, केवल रांची और जमशेदपुर के ही आकलन के हमारी सरकार ने स्वीकार किया है और उसे स्वीकार्यता के संदर्भ में हमने एप्रूव करके जो भी रिलीज है, उसको जारी किया है। इस नाते वहां जो और भी कॉलेज हैं, उनके लिए भी पहल की गई है, जैसे रांची में रांची कॉलेज को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की कार्रवाई, कोल्हान विश्वविद्यालय के infrastructure के लिए अनुदान, जमशेदपुर में महिला कॉलेज और करीम सिटी के कॉलेज के लिए infrastructure में अनुदान, रांची के सेंट ज़ेवियर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, रांची और जमशेदपुर में नए इंजीनियर कॉलेज खोलने के लिए अनुदान, तो वहां इतने व्यापक परिवेश में कार्रवाई की गई है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा का स्तर बढ़े तथा नौजवानों का उस ओर रुझान हो, इस नाते इसकी पूरी चिंता की गई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः उपसभापति जी, मेरे सवाल को appreciate नहीं किया गया है। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि वह क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। वहां राज्य सरकार का व केन्द्र सरकार का हजारों करोड़ रुपया, हर साल नक्सलवाद के ऊपर खर्च होता है। मैं जो कहना चाहता था, मेरे सवाल का जो एक background था, वह यह था कि क्यों न इस क्षेत्र को शिक्षा का एक hub बनाया जाए, ताकि वहां के लोकल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, वहां का आर्थिक विकास हो, ताकि नक्सलवाद के ऊपर लगाम लग सके।

श्रीमान् जी, झारखंड में आपकी सरकार है, वहां के कॉलेजों में professors नहीं हैं, lecturers नहीं हैं और स्कूलों में teachers नहीं हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं और हाजिरी लगाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। आपने कहा है कि आपने उच्चतर शिक्षा अभियान में 133 करोड़ रुपया release किया है। यह 133 करोड़ रुपया मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इतने institutes के ऊपर है, university convert कर दी जाएगी, कॉलेज को बढ़ा दिया जाएगा, होस्टल बना दिया जाएगा, खेल का मैदान बना दिया जाएगा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, जिसने देश को महेन्द्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी जैसे ओलम्पिक खिलाड़ी दिए हैं। मान्यवर, मैं खुद MIT, रोचेस्टर में गया था और मुझे सुनकर और मिलकर बड़ी खुशी हुई कि BIT, Mesra, रांची का एक बच्चा वहां प्रोफेसर है। वह वहां के बच्चों के पेपर्स चैक करता है और वह स्टूडेंट है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your questions.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः मेरे सवाल की भूमिका को थोड़ा appreciate करिए। यह तो आपका एक stereotype reply है, वह मैंने पढ़ लिया। उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं भी मंत्री रहा हूं और हम लोगों ने भी जवाब दिए हैं, लेकिन हमने ऐसा जवाब नहीं दिया है। मैं आप से request करूंगा कि आप प्रश्न के मूल तक जाएं और झारखंड में रांची और जमशेदपुर को educational hub बनाने के लिए और funds का प्रावधान करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a suggestion.

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेयः महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव स्वागत योग्य है और पूरी मर्यादा से हम इस सुझाव को ले रहे हैं, लेकिन educational hub बनाने या डेवलप करने के संबंध में अगर राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उस में पूरा सहयोग कर केन्द्र सरकार ध्यान देगी।

श्री महेश पोद्दारः महोदय, मैं रांची, झारखंड का ही हूं। हमारे यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईएम, ट्रिपल आईटी और अभी-अभी डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। इसमें आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई सालों से चल रही है, लेकिन उनका वहां अपना कोई campus नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कब तक इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अपने campus हो जाएंगे, जिनमें वे अपने functions करना शुरू कर पाएंगे? मैं प्रेम चन्द गुप्ता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने झारखंड के खिलाड़ियों की चर्चा की है। महोदय, वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात बहुत दिनों से हो रही है क्योंकि यह सभी लोग मानते हैं कि वहां खेल प्रतिभा काफी है। उस बारे में यदि कोई प्रस्ताव हो तो मंत्री जी कृपया हमें जानकारी देने का कष्ट करें।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेयः महोदय, माननीय सदस्य का विचार बहुत ही श्रेष्ठ है और महोदय, मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि जो योजनाएं हमारी सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर शुरू की हैं, उनमें झारखंड जैसे राज्य को भी प्राथमिकता दी गयी है। वहां राज्य के लिए बजट allocation भी जहां राज्य ने 133 करोड़ कहा, उसे बढ़ाकर टोटल बजट allocation 216 करोड़ कर दिया है, लेकिन अभी जो आईआईएम का विषय है, अगर वहां राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी तो मैं जिम्मेदारी से उत्तर दे रहा हूं कि हम 3 साल में वहां आईआईएम का निर्माण कराएंगे।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः महोदय, झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था तब रांची को

educational hub के रूप में लोग जानते थे और पूरे बिहार के लोग भी अपने बच्चों को रांची में स्कूलिंग के लिए भेजते थे, लेकिन अब झारखंड राज्य बनने के बाद परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। वहां अब स्कूलिंग के बाद करीब-करीब 45 परसेंट से ज्यादा बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पुणे या बंगलुरु चले जाते हैं क्योंकि वहां इस तरह की सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी योजना है, जिससे कि हमारे यहां के 45 परसेंट बच्चे जो पुणे या बंगलुरु में पढ़ाई के लिए जाते हैं, चाहे वह प्रोफेशनल पढ़ाई हो या कॉलेज की पढ़ाई हो, उसे रोकने के संबंध में क्या सरकार की कोई प्लानिंग है?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : महोदय, माननीय सदस्य का विचार अच्छा है। मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि हमारी सरकार ने "रूसा" के तहत कार्य-योजनाएं ली हैं, उन कार्य-योजनाओं को झारखंड में और विशेषकर रांची, जमशेदपुर में विशेष प्राथमिकता दी गयी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि अब अध्ययन के लिए बच्चों का केन्द्रीयकरण वहीं बना रहेगा, ऐसा हम सब को विश्वास है।

SHRI BISHNU CHARAN DAS: Mr. Deputy Chairman, Sir, during the last financial year, the Central Government had announced that it would provide funds for the development of the three medical colleges in Odisha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But this question pertains to Jharkhand.

SHRI BISHNU CHARAN DAS : May I know from the hon. Minister how much funds they had announced and how much funds they have provided for medical colleges in Odisha?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want, you can answer.

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेयः उपसभापति जी, माननीय सदस्य का प्रश्न, मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। अगर वे अलग से इसको सूचित करेंगे, तो हम इसकी सूचना लेकर उनको इसका उत्तर दे देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 200. Shri Palvai Govardhan Reddy. He is not present. Any supplementaries?

[The questioner Shri Palvai Govardhan Reddy was absent.]

Number of houses needed in Telangana by 2020

*200.SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) the estimated shortage of urban housing in the country as of 2015 and what would be the expected increase by 2020;

(b) whether any latest assessment has been made by the Ministry to find out the urban housing in the country and if so, the details thereof;

(c) what incentives the Ministry is proposing and also impressing upon States to provide for making 'Housing for All' dream a reality; and